चौधरी चरण सिंह अभिलेखागार

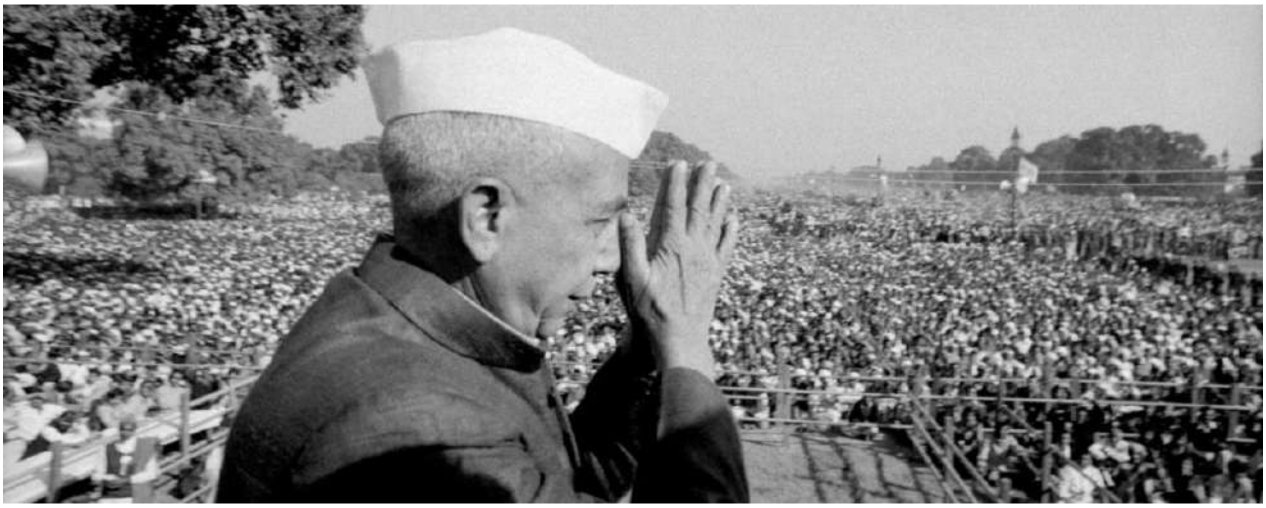

चौधरी चरण सिंह का जीवन इतिहास

http://chaudharycharansingh.org

१७०७ - १८६०

तेवतिया कुटुम्ब ने बल्लभगढ़, फरीदाबाद में अपना प्रभाव बढ़ाया। १८५७ के क्रांतिकारी नाहर सिंह को उनके क्रांतिकारी भूमिका के लिए अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, उन्हीं के वंशज बादाम सिंह यमुना पार चले आये।

१७०७ - १८६० तेवतिया कुटुम्ब ने बल्लभगढ़, फरीदाबाद में अपना प्रभाव बढ़ाया। १८५७ के एक क्रांतिकारी नाहर सिंह को उनके क्रांतिकारी कार्यों के लिए अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, उन्हीं के वंशज बादाम सिंह यमुना पार कर आये। तेवतिया, मेहनतकश जाट समुदाय के किसानों का एक गोत्र, बल्लभगढ़ जिले के सीही ग्राम (दिल्ली के दक्षिण में आज के हरियाणा में) रहते थे। मुग़ल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मुग़ल साम्राज्य के सिकुड़ने के साथ ही उन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया। मुग़ल दरबार की ओर से गोपाल सिंह को १/१६ के अनुपात सेमालगुजारी वसूलने का दायित्व सौंपा गया, और इस प्रकार उसके गोत्र के प्रभाव बढ़ने की शुरूआत हुई।

अगले १५० वर्षों के दौरान तेवतिया स्थानीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाता रहे, गोपाल सिंह के वंशज नाहर सिंह (१८२३-१८५८) छोटी सी रियासत बल्लभगढ़ (जिसमें १२१ गांव शामिल थे) के प्रमुख बने, और १८५७ के आज़ादी के समर में एक क्रांतिकारी भूमिका निबाही। अंग्रेजों द्वारा उनको पकड़ कर, उनके १७ साथियों सहित, चांदनी चौक में फांसी पर लटका दिया गया। उनकी इस असफल क्रांति के चलते उनके कबीले के लोगों को अंग्रेजी फ़ौज की लूटपाट और कोप से बचने के लिए बल्लभगढ़ से दूर सुरक्षित गांवों में शरण लेनी पड़ी (जाट वंशजों के ऐतिहासिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है) ऐसे ही उनके वंशज बादाम सिंह भविष्य की नई संभावनाओं को देखते हुए यमुना के पार ६० किलोमीटर दूर अपने संगोत्रीय भटौना गांव, जो गंगा के इधर सीही गांव से ३० किलोमीटर पड़ता था (गंगा-यमुना के दोआब में) आ बसे । उनके पांच बेटे थे, सबसे बड़े लखपत सिंह और सबसे छोटे मीर सिंह।

२३ दिसम्बर १९०२

चरण सिंह ने २३ दिसम्बर को नेत्र कौर और मीर सिंह के यहाँ जन्म लिया

मीर सिंह (१८ वर्ष) का नेत्र कौर (बुलंदशहर ज़िला के चितसोना अलीपुर गांव) से १८९८ में विवाह संपन्न हुआ। यह परिवार १५ किलोमीटर उत्तर में ५ एकड़ जोत पर पट्टे पर खेती करने के लिए नूरपुर गांव आ पहुंचे।

१९०३ - १९२१

प्रतिभाशाली किसान मीर सिंह के पुत्र चरण सिंह की शिक्षा का श्रीगणेश जानी खुर्द से हुआ।

युवा, प्रतिभाशाली और कर्मठ किसान मीर सिंह ने पट्टे पर ली कृषि भूमि की काया पलट कर दी। अब भूस्वामी इसे ऊँची कीमत पर, जिसे अपने पसीने के बल चुकाना मीर सिंह के बूते की बात न थी, बेचना चाहता था। मीर सिंह को इसे छोड़ना पड़ा। मीर सिंह शिशु चरण सिंह को लेकर ६० किलोमीटर उत्तर में संगोत्रीय गांव भूपगढ़ी में

आ बसे, जहाँ यह परिवार १९२२ तक रहा। उनके भाई २० किलोमीटर दक्षिण में एक अन्य संगोत्रीय गांव भदौला में आ बसे, दोनों गांव मेरठ जिले में पड़ते हैं। चरण सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा भूपगढ़ी से दो किलोमीटर दूर जानी खुर्द में ग्रहण की, जहाँ वह प्रतिदन जाते थे। वह घर पर गांव के दूसरे बालकों की ही तरह थे : घर के काम-काज में हाथ बंटाना, गंडासे से पशुओं के लिए चारा काटना, कबड्डी खेलना। गांव के स्कूल की क्षमताएं सिमित होती हैं, अतः तीक्ष्ण बुद्धि चरण सिंह को एक साल के लिए १५ किलोमीटर दूर मेरठ के मॉरल ट्रेनिंग स्कूल में जाना पड़ा। इसके बाद १९१४ में मेरठ के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लिया। नवीं कक्षा में उन्होंने विज्ञानं विषय चुना, साथ ही अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और इतिहास में भी रुचि दिखाई। स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व तथा कार्यक्रमों ने किशोर चरण सिंह को समान रूप से प्रभावित किया।

चरण सिंह ने १९१९ में मैट्रिक्युलेशन (हाई स्कूल) की शिक्षा पूरी की और १९२१ में इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास की। उन पर ओजस्वी हिन्दू राष्ट्रवादी कविताओं की रचना करने वाले हिन्दी कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता "भारत भारती" और अप्रैल १९१९ में अमृतसर मैं घटित 'जलियांवाला बाग़' कांड ने गहरे तक प्रभावित किया।

ताऊ लखपत सिंह का अध्ययनशील, होनहार चरण सिंह पर विशेष स्नेह था। उन्हें पता चला कि उनके प्रिय भतीजे की पढ़ाई उसके पिता की आर्थिक तंगी के चलते बाधित हो सकती है। उन्होंने वादा किया कि चरण सिंह की पढ़ाई पूरी करने तक उनकी शिक्षा का व्यय वह उठायेंगे।

१९२२

मीर सिंह मेरठ जिले में भदौला गांव चले आये, जहाँ उन्होंने अपनी बाकी जिन्दगी गुज़ारी

खेती के लिए जमीन का एक अच्छा टुकड़ा भदौला में २१,००० रुपये में उपलब्ध था, लखपत सिंह चाहते थे कि मीर सिंह भी वहां आ जायें। उनके दो भाई ब्रिटिश सेना में थे और उन्होंने १८९९-१९०२ में अफ्रीका के बोअर युद्ध में भाग लिया था; उनके वेतन और पेंशन से पेशगी की रकम ७,००० रुपये देने में मदद मिली। बकाया रकम का भुकतान करने तक आगे के खातों में ज़मीन असली मालिक के स्वामित्व में ही रही। परिवार एक बार फिर इकट्ठा हो गया, संयुक्त परिवार ने हो ज़मीन पर मेहनत शुरू की, अपनी उद्यमी प्रवृत्ति और कृषि-अनुभव के चतले जमीं को उर्वर बनाने, हर-भरा बनाने में मीर सिंह ने मार्ग दर्शन किया, यह लगभग २१ एकड़ ज़मीन थी, जिसे चरण सिंह और उनके दो भाइयों ने १९६१ में बेचा।

१९२३

चरण सिंह ने आगरा कॉलेज से विज्ञान में डिग्री प्राप्त की

आगरा कॉलेज, आगरा, उत्तर प्रदेश से वो विज्ञान की स्नातक की डिग्री लेते हैं।

१९२५

चरण सिंह ने आगरा कॉलेज से इतिहास में मास्टर ऑफ आर्टस (स्नातकोत्तर) डिग्री प्राप्त की, गायत्री देवी से विवाह

आगरा कॉलेज, उत्तर प्रदेश, से इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि मास्टर्स डिग्री) प्राप्त की। ब्रिटेन, फ्रांस और

भारत के इतिहस तथा का अध्ययन किया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कबीर का अध्ययन किया और इस संत कवि के अनेक दोहों को याद किया और सद्प्रभाव डालने हेतु ग्रामीणों लगातार होने वाली बात-चीत में उनका उपयोग किया। एक भंगी जाती के व्यक्ति के हाथ का बना खाना खाया, फलस्वरूप हॉस्टल में सहपाठियों द्वारा वहिष्कार झेलना पड़ा, किन्तु वह अपने निर्णय पर अडिग रहे। २५ जून को रोहतक के गढ़ी कुण्डल गांव में गायत्री देवी से विवाह हुआ।

१९२६ - १९२७

आगरा विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की

मेरठ कॉलेज से कानून की डिग्री (एल.एल.बी.) हासिल की (तब मेरठ आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था), बड़ौत के जाट स्कूल तथा लखावटी के जाट डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर काम करने से मना कर दिया, जब तक कि वे अपने साथ लगे "जाट" शब्द को न हटायें। उक्त संस्थानों ने ऐसा नहीं किया।

१४ सितम्बर १९२७ को सबसे बड़ी बेटी सत्य वती का जन्म हुआ।

१९२८

ग़ाजियाबाद शहर में दीवानी से वकालत की शुरूआत की

मेरठ जिले के गाजियाबाद शहर में दीवानी के मुकदमों से वकालत शुरू की। साइमन कमीशन के विरोध के साथ अपनी पहली राजनितिक कार्यवाही की शुरूआत की।

१९२९

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जहाँ वह १९६७ तक रहे

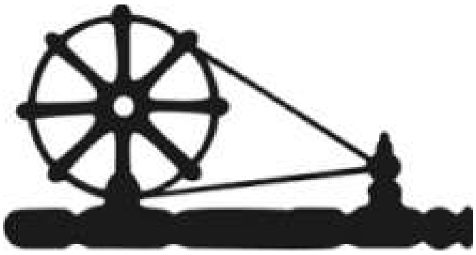

२७ वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली, गाज़ियाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की, जिसमें १९३९ तक अनेक पदों पर रहे।

१९३०

आर्य समाज और कांग्रेस दोनों में सक्रिय, सामाजिक एवं राजनितिक परिवर्तन/बदलाव की गतिविधियाँ साथ-साथ जारी रहीं

१९३९ तक गाज़ियाबाद आर्य समाज समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष या महासचिव रहे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में पूरी सक्रियता से भागीदारी की, ५ अप्रैल को ६ माह के लिए पहली बार जेल गए। मेरठ डिस्ट्रिक्ट से निर्विरोध चुने गए, जहाँ १९३५ तक कनिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष पद पर रहे।यहीं से गांधी जी की सोच और आदर्शों ने उन्हें और अधिक आकर्षित किया और वह पूर्णतः उनके प्रभाव में आ गये :
अहिंसक क्रांति, सामाजिक बदलाव, हरिजनों का उत्थान, सत्याग्रह,

वलिदान, आत्म संयम, सादगी एवं खादी। "सत्य ही धर्म है" के नारे को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, और यहाँ से ईमानदारी, निर्भयता, कड़ी मेहनत तथा वचनबद्धता उनके जीवन की नीव बन गए. उनके लिए दयानंद की सामाजिक परिवर्तन, कबीर का आकारहीन आकर्षण, दोनों गांधी के राजनीतिक क्रांति में सिमट गए

१७ सितम्बर को दूसरी पुत्री वेद वती का जन्म

१९३२

"कम्युनल अवार्ड" के विरुद्ध आंदोलन किया

"कम्युनल अवार्ड" के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन में भाग लिया। एक दलित को अपने घर रसोइया रखा, जो १९३९ तक उनके साथ रहा।

२३ सितम्बर को तीसरी पुत्री ज्ञान वती का जन्म

१९३७

संयुक्त प्रान्त धारा सभा के लिए पहली बार चुने गए, १९७७ तक इस विधान सभा के सदस्य रहे।

१९३७ में संयुक्त प्रांत धारासभा के लिए कांग्रेस के टिकट पर मेरठ जिले (दक्षिण-पश्चिम), जिसमें तहसील बाग़पत और गाज़ियाबाद शामिल था, पहली बार चुने गए। कुल मतों के ७८.०६ प्रतिशत मत हासिल कर नेशनल पार्टी के प्रत्याशी को हराया। (तब मेरठ , मुज़फ्फरनगर और मथुरा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आते थे) इस विधानसभा क्षेत्र का लगातार आठ बार प्रतिनिधित्व किया, यथा- १९३७, १९४६, १९५२, १९५७, १९६२, १९६७, १९६९ और १९७४ ।

२३ फरवरी को चौथी पुत्री सरोज का जन्म हुआ।

१९३८ - १९३९

कांग्रेस विधान मंडल दल और विधान सभा में प्रगतिशील एवं किसान–हितैषी विधेयक प्रस्तुत करने में सक्रिय। १९३९ में गाजियाबाद से मेरठ आ गए।

उत्पादक के हितों की रक्षा और आढ़तियों तथा व्यापारियों के उत्पीड़न से उन्हें बचने के लिए उत्तर प्रदेश धारासभा में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल (कृषि उत्पादन विपणन बिल) प्रस्तुत किया। यद्यपि निहित स्वार्थों के चलते यह बिल पारित न हो सका, बहुत बाद में जब िफ १९६४ में प्रदेश के कृषि मंत्री बने, तब जाकर पारित हुआ। कहते हैं की चरण सिंह द्वारा प्रस्तुत इस बिल के प्रारूप पर आधारित पंजाब सरकार ने अपने यहां मंडी समिति एक्ट १९४० में ही पारित कर दिया था।

संयुक्त प्रान्त के प्रभावी प्रशासन में, विशेषकर पुलिस एवं लोकसेवा के क्षेत्र में प्रगति के अभाव के कारण, मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत के समक्ष विरोध प्रकट करने के लिए कांग्रेस के विधायकों के दबाव गुट का नेतृत्व किया।

०५ अप्रैल १९३९ को कांग्रेस विधान मंडल दल की कार्यसमिति के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसमें खेती करने वालों और किसान-संतानों एवं आश्रितों के लिए लोक सेवा के अन्तर्गत रिक्तियों में ५०% का आरक्षण दिए जाने की मांग की गई। हालाँकि पार्टी द्वारा उदासीनता बरतते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

उन्होंने जमींदारी उन्मूलन के विषय का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। वह भूमि-उपयोग बिल का व्यवस्थापन करते हैं, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार बिल की प्रस्तावना करते हैं, साथ ही भूमि का मालिकाना हक़ उन काश्तकारों अथवा भूमि को वास्तविक रूप से जोतने वालों के पक्ष में हस्तांतरित करने की मांग करते हैं जो उनके द्वारा जोती गई भूमि के वार्षिक लगान का दस गुना देने पर सहमत हैं। इस बिल का ज़मींदारों ने कड़ा विरोध किया। फलस्वरूप इसे विधान सभा में नहीं रखा जा सका । उन्होंने काश्तकारों के हितों की रक्षा में एवं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेकों उपाय सुझाये तथा इस विषय में कई लेख प्रकाशित किये। इसके साथ ही कांग्रेस विधान मंडल दल के समक्ष , शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक अथवा किसी भी सरकारी सेवा में भर्ती के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति को छोड़कर हिन्दू की किसी भी अन्य जाति के बारे में पूछताछ पर निषेध प्रस्तावित किया।

काश्तकारों को सहायता उपलब्ध करने के उद्देश्य से, जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसानों को ऋण और ऋणदाता साहूकारों के चंगुल से मुक्त करने हेतु संयुक्त प्रांत कृषि काश्तकार एवं कामगार ऋण विमोचन बिल के व्यवस्थापन एवं पारित कराने में प्रमुख भूमिका निभाई और हजारों-हजार किसानों को उनकी भूमि को सार्वजनिक नीलामी से बचाकर लाभ पहुँचाया।

कांग्रेस सरकार के नवंबर में त्यागपत्र देने के बाद, १९३९ में वह ग़ाज़ियाबाद से मेरठ आ गए। १९४६ तक मेरठ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अथवा महासचिव पद पर रहे। किसान-काश्तकारों के हितों के लिए प्रमुख प्रवक्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के समक्ष एवं विधान मंडल में उनकी ओर से अनेक प्रस्ताव रखे।

१७ जुलाई १९३७ से २ नवंबर १९३९ तक संयुक्त प्रांत धारासभा जारी रही ।

१२ फरवरी १९३९ को पांचवे पुत्र अजित सिंह का जन्म।

१९४०

व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरन एक साल बरेली जेल में

व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान एक साल के लिए दूसरी बार जेल गए। पहले मेरठ केन्द्रीय कारागार में डाले गए, फिर बरेली केन्द्रीय कारगर में भेज दिए गए, अक्टूबर १९४१ में रिहा किये गए। बच्चों में अच्छे आचार-विचारों को रोपने के लिए जेल से पत्रों की श्रृंखला लिखी "शिष्टाचार"।

१९४६ तक मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं अध्यक्ष रहे।

१९४२

"भारत छोड़ो आंदोलन" के दौरान १३ माह के लिए पुनः जेल भेजे गए, छोड़े जाने पर पुनः दीवानी वकालत शुरू की

"भारत छोडो आंदोलन" के दौरान २३ अक्टूबर १९४२ से नवम्बर १९४३ के अंत तक तीसरी बार जेल गए। जेल

भेजे जाने से पहले उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में गाज़ियाबाद, हापुड़, मवाना, सरधना और बुलंदशहर के इलाकों में भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया, रिहा होने पर पुनः वकालत शुरू कर दी किन्तु बहुत अच्छी नहीं चली, क्योंकि जिन्हें वह झूठा फर्जी समझते थे, उन केसों को नहीं लेते थे। परिश्रम और गरीबी की जिंदगी जीते हरे। कथित रूप से वह कहते हैं कि "वकील होने के नाते यह उनकी मज़बूरी/बाध्यता है, किसी लाभ के लिए वह यह काम नहीं नहीं करते।"

जो उन्हें जानते हैं, उनके लिए जीवन शैली की सादगी "उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी सादगीपूर्ण जीवन शैली से भलीभांति परिचित रहा। यद्यपि वह कोई अनुभवहीन या भोले-भाले किसान नहीं थे। चरण सिंह अपने अधिकांश राजनीतिक साथियों तथा विरोधियों की अपेक्षा बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ थे, जबकि आज़ादी पूर्व के नेताओं में बहुत से उच्च शिक्षित थे। " - पॉल आर. ब्रास, पृष्ठ ८२

छठी एवं अंतिम संतान, पुत्री शारदा का जन्म २३ दिसम्बर को हुआ

१९४५

संयुक्त प्रांत में बसी ८५% से ऊपर ग्रामीण आबादी के प्रति प्रशासन को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व एवं दायित्वपूर्ण बनाने की दृष्टि से खेतिहरों को सरकारी सेवाओं में लेने का प्रस्ताव रखा

आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बनारस के किसानों की मीटिंग में कांग्रेस के घोषणा-पत्र में जमीदारी उन्मूलन की दृष्टि से भूमि और कृषि पर एक मसौदा तैयार किया, जो दिसंबर में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग में एक प्रस्ताव के रूप में पारित हुआ। इसी दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं, खेतिहरों को सरकारी नौकरियों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा किन्तु इस प्रस्ताव को न तो कांग्रेस न ही सरकार का समर्थन मिल पाया।

१९४६

गोविन्द बल्लभ पंत (१८८७–१९६१) संयुक्त प्रान्त के प्रीमियर (मुख्यमंत्री) चुने गए

BACK TO TOP

गोविंदबल्लभ पंत (१८८७-१९६१) संयुक्त प्रान्त के प्रीमियर मुख्यमंत्री) चुने गए। चरण सिंह उन्हें अपने पिता समान मानते थे, और उस दौर को, जब उन्होंने जी.बी. पंत के साथ काम किया (१९४६-१९५४) अपने जीवन का "सुनहरा दौर" मानते हैं। (१९८१ में दिल्ली में एक भाषण के दौरान)

१९४६

चरण सिंह दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए मुख्यमंत्री गोविंदबल्लभ पंत के संसदीय सचिव चुने गए

गोविंदबल्लभ पंत (१८८७-१९६१) संयुक्त प्रान्त के प्रीमियर (मुख्यमंत्री) चुने गए। चरण सिंह उन्हें अपने पिता सामान मानते थे, और उस दौर को, जब उन्होंने जी.बी. पंत के साथ काम किया (१९४६-१९५४) अपने जीवन का "सुनहरा दौर" मानते हैं। (१९८१ में दिल्ली में एक भाषण के दौरान)

वह उत्तर प्रदेश धारा सभा के लिए मेरठ जिले (दक्षिण-पश्चिम) से

दोबारा चुने गए। उन्होंने चुनाव आम जनता से लिए पैसे से लड़ा - अमीरों से कोई पैसा नहीं लिया, अपने पूरे राजनितिक जीवन में वह इस आदर्श पर कायम रहे।

गोविन्द बल्लभ पंत की कांग्रेस सरकार में वह संसदीय सचिव नियुक्त किये गए। सरकार में ६ मंत्री और लालबहादुर शास्त्री (बाद में भारत के प्रधानमंत्री) एवं चन्द्रभानु गुप्त (उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री तथा चरण सिंह प्रमुख राजनितिक विरोधी) सहित १२ संसदीय सचिव थे।

१९५१ तक स्वास्थ्य मंत्री, स्थानीय निकाय, और अंततः प्रीमियर (तब मुख्यमंत्री को यही बोला जाता था) के तहत संसदीय सचिव पद पर रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (इ.आई.सी.सी.) के सदस्य रहे। उन जमीनों से जिन्हें काश्तकार जोत रहे थे, बेदखली से संरक्षण के लिए, यू.पी. काश्तकारी अधिनियम में संशोधन किया तथा एक जनवरी १९४० से बेदखल किये गए सभी काश्तकारों को बहाल करवाया।

कांग्रेस संगठन की कमजोरियों यथा-- उच्च शहरी जातियों के हाथों नेतृत्व, जातिवाद, व्यक्तिगत विरोध, स्वार्थपरायणता, एकता का अभाव, कमजोरों का दमन और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को आंदोलन के तौर-तरीकों में शामिल करने से लेकर समस्याओं की न जानकारी और भारत की गहरी पैंठी समस्याओं को हल करने की दिशा में असफल रहना।

१९४७

अपनी कई पुस्तकों में से सबसे पहली पुस्तक – "एबोलिशन ऑफ़ ज़मींदारी : टू अल्टरनेटिव" का प्रकाशन

अपनी कई पुस्तकों में से सबसे पहली पुस्तक- "एवोलिशन ऑफ जमींदारी : टू अल्टेरनेटिव्स" का प्रकाशन "एवोलिशन ऑफ़ जमींदारी : टू अल्टेरनेटिव्स" का प्रकाशन। भारत खेतिहर कृषकों एवं कृषि पर चरण सिंह के विचार, जो विश्वव्यापी प्रवृत्तियों से गहरे प्रभावित थे, आकार लेने लगे थे। यह उनकी पहली पुस्तक है, और उनके अध्ययन का मापदंड है, जैसा कि ग्रंथ सूची से जाहिर है (नीचे देखें)

चरण सिंह ने अपनी इस पहली पुस्तक का प्रकाशन उस दौरान कराया, जब वे मुख्यमंत्री गोविन्दबल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त प्रांत ज़मींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। (१४ नवम्बर १९४६ से ३ जुलाई १९४८ तक)

- **हब्बार्ड, लियोनार्ड.** इकोनॉमिक्स सोवियत अग्रीकल्चर, लन्दन : मैकमिलन एण्ड कं० लि० १९३९
- **मार्क्स, कार्ल.** द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो (बाद में मेनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी) १९४८
- **मार्क्स, कार्ल.** दास कैपिटल : क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनोमी १८६७
- **लेनिन, ब्लादिमिर.** सलेक्टेड वर्क्स
- **बिरजी, प्रोफेसर.** इटैलियन कैम्पेना, १९३३ (उपलब्ध नहीं)
- **लीग ऑफ नेशन्स.** यरोपियन कॉन्फ्रेंस आफ रूरल लाइफ, जेनेवा, १९३९
- **होवे, फ्रेडरिक सी. डेन्मार्क.** ए कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ, लन्दन : एलेन एंड अनविन, २०३ पृष्ठ, १९२२
- **एडिसन, क्रिस्टोफर लॉर्ड.** ए पॉलिसी फार ब्रिटिश एग्रीकल्चर : १९३९
- **वारिनर, डोरीन.** इकॉनोमिक्स ऑफ पीजेंट फार्मिंग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९३९
- **फेई, डॉ० शियाओ तुंग.** पीजेंट लाइफ इन चाइना, लंदन, केगन पॉल, १९३८
- **बक, जॉन लॉसिंग.** चाइनीज फार्म इकॉनोमी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, १९३०
- **स्नो, एडगर.** रेड स्टार ओवर चाइना, रेंडम हाउस, १९३८

- **हिंडस, मौरिस गारशकॉन**. द ग्रेट ओफेन्सिव, न्यूयार्क : हैरिसन, स्मिथ एण्ड रॉबर्ट हास, १९३३ (अथॉरिटी ऑन सोवियत एण्ड सोवियत यूरोप)
- **वान डेर पोस्ट.** ए. पी. द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी १९३७
- **जॉर्डन, विर्जिल.** विजनेस मेंस कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोर्ड एण्ड ऑफ कॉमर्स ऑफ द यू. एस. ए. न्यूयार्क १९२६
- **कौटिल्य,** अर्थशास्त्र
- **पॉवेल, बड़ेन** (१८८१-८२) कोटेड इन द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- **काये, जॉन विलियम्स** एफ आर एस ए हिस्ट्री ऑफ द सेपॉय वार इन इंडिया, १८५७-५८, लंदन, लोंगमेन्स, ग्रीन १८७५
- **गांगुली, एन.** द इंडियन पीजेंट , लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९३३
- **नानावती, सर मणिलाल बल्लभ भाई एण्ड अंजारिया, जसवंत रॉय जाजन्तीलाल,** द इंडियन रूरल प्रॉब्लम, इंडियनसोसाइटी ऑफ़ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स १९४४
- **मसानी, मोंश्येर रुस्तम "मीनू".** सोशलिज्म रिकन्सिडर्ड, बॉम्बे पद्म पब्लिकेशन, १९४४
- **मम्फोर्ड लेविस,** टेक्नीक्स सिविलाइजेशन हरकोर्ट, ब्रेस एण्ड कम्पनी, पी पी ४९५, १९३४ ("अमेरिकन फिलॉसफर एण्ड हिस्टोरियन ऑफ़ टेक्नोलॉजी ....इट इस द मॉरल, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल च्वाइस वी मेक, नॉट द मशीन्स वी यूज़, मम्फोर्ड आरग्यूज, दैट हैव प्रोडयूस्ड ए कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीअलाइज्ड मशीन-ऑरियन्टेड इकोनॉमी, हूज इम्पर्फेक्ट फ्रूट्स सर्व द मजोरिटी सो इम्पर्फेक्टली"
- **मम्फोर्ड, लेविस दि** कल्चर ऑफ़ सिटीज़ , न्यूयार्क : हरफोर्ट, ब्रेस एण्ड कम्पनी , १९३८ ("लेसिस मम्फोर्डस द कल्चर ऑफ़ सिटीज़ इज़ ए क्लासिक ..... वाज द फर्स्ट एण्ड रिमेन्स दि बेस्ट बुक ऑन द कल्चर ऑफ़ सिटीज" मम्फोर्ड एडवोकेटेड 'डिसेंट्रलाइजेशन' एण्ड अर्न्ड ए रेपुटेशन फॉर हेटिंग लार्ज सिटी')
- **स्ट्राचे, जॉन.** द थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ़ सोशलिज्म, लंदन : विक्टर गोलांज, १९३६, पृष्ठ ४८८
- **ऑथर नॉट फाउंड,** द लैंड एण्ड पीजेंट इन रूमानिया
- **कोले, जी. डी. एच.** प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स, लंदन, पेलिकन बुक्स १९३७ (सोशलिस्ट, एन इंग्लिश पॉलिटिकल थिओरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, राइटर एंड हिस्टोरियन)
- **शूमेन, फ्रेडरिक एल.** हिटलर एण्ड द नाजी डिक्टेटरशिप, न्यूयार्क : एल्फ्रेड ए नॉफ, पी. पी. ५५८, १९३५ (वाज ए हिस्टोरियन, एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एण्ड इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर)
- **वार्न्स, डा. डब्लू.** टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ़ एग्रीकल्चरल डवलपमेंट इन इंडिया, ए नोट,गवर्नमेंट प्रेस, लाहौर १९४३, पृष्ठ १२७ +
- **दांतेवाला, प्रो. एम. एल.** गाँधिइज्म रिकन्सीडर्ड; बॉम्बे; पद्म पब्लिकेशन १९४४ (लीडिंग इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, १९०९-१९८७)
- **मुखर्जी, डॉ० राधाकमल,** फूड प्लानिंग फॉर ४०० मिलियंस, १९३८ (राधाकमल मुखर्जी , १८८९-१९६८)..... कन्सीडर्ड ए पॉयनियर इन सोशियोलॉजी, इन इंडिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाज ए मेजर सेंटर ऑफ़ सोशियोलॉजी एण्ड सोशल एन्थ्रोपॅलॉजी, अंडर द स्कॉलरशिप ऑफ़ द ट्रंबीरेट। .... लखनऊ सून इमर्जड एज ए लीडिंग सेंटर फॉर सोशल साइंस स्टडीज एण्ड इट रिमेंड सो अनटिल द मिड- १९६०'ज़ ")
- **मुखर्जी, डा० राधाकमल,** इंडिया एनलाइज्ड १९३४
- **श्री धरणी, कृष्णलाल,** द महात्मा एण्ड द वर्ल्ड, न्यूयार्क : डुएल, स्लान एण्ड पियर्स, १९४६
- **नारायण जयप्रकाश;** व्हाई सोशलिज्म? ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी, १९३६
- **काटजू, कैलाशनाथ,** माई लाइफ एट द इंडियन बार १९४५
- **गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया,** यू. पी. एग्रीकल्चरल रिऑर्गनाइजेशन कमेटी , १९३९ - ४१
- **गवर्नमेंट ऑफ़ ब्रिटिश** एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन, १९२३

- **लीग ऑफ़ नेशंस** पब्लिकेशन्स १९४०
- " एग्रीकल्चरल डेब्ट रिडम्पशंस एण्ड आफ्टर भावनगर स्टेट", १९३७
- **नानावती, सर मनीलाल बी.** "फाइनल रिपोर्ट ऑफ़ द फेमीन इन्क्वायरी कमीशन", १९४५

१९४८

"संयुक्त प्रांत में जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट" तैयार करने में सहायता की, जो स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार कानून में मील का पत्थर सिद्ध हुई।

१९५६ तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल दल के महासचिव रहे। मुख्यमंत्री जी. बी. पंत की अध्यक्षता में संयुक्त प्रांत जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट तैयार करने में भागीदारी की, जिसमें राजस्व मंत्री हुकुम सिंह उपाध्यक्ष और चरण सिंह मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव रहे। चरण सिंह ने मुख्यमंत्री जी.बी. पंत को १७ पृष्ठों की एक वय व्यक्तिगत असहमति- टिप्पणी लिखी, इसका अवलोकन कर पंत जी ने उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और इस प्रकार विधेयक पुनः तैयार किया गया। वह विधेयक के प्रमुख वास्तुकार बने और इसी क्रम में राजनीतिक दलों के दांये और बांये खेमों से होने वाले आक्रमणों से इस विधेयक के प्रमुख बचावकर्ता भी।

"उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन : आलोचनाएँ और जवाब" इसने सरकार और खुदकाश्त करने वाले किसानों के बीच से बिचौलियों के रूप में कायम ज़मींदारों को समाप्त कर दिया और एक शांतिपूर्ण एवं सामाजिक ढांचे में शांति की स्थापना की। जिन ज़मीनों पर भूमिहीनों (अनुसूचित जाति एवं दलितों) ने घर बना रखे थे ऐसे लाखों लोगों को घरों का स्वामी बना दिया; उत्तर प्रदेश में ज़मींदारों को ज़मीन पर पुनः कब्जे का अधिकार नहीं दिया गया (अन्य अधिकांश राज्यों की भांति); और लाखों किसानों को राज्य का सहभागी बनाते हुए लगातार बढ़ रहे समाज के लोकतान्त्रिक ढांचे को मजबूत बनाया, निर्धन-भूमिहीन ग्रामीणों का मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा बना रहा।

४ अगस्त १९५१

उत्तर प्रदेश के न्याय एवं सूचना मंत्री बने।

४ जून से ८ अगस्त तक एवं सूचना मंत्री रहे। ९ अगस्त १९५१ से १९ मई १९५२ तक कृषि, पशु पालन और सूचना मंत्री के पदों पर रहे।

१९५२

उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि सुधार विधेयक पारित कराया, जिसने उन्हें गांवों और किसानों के प्रतिनिधि के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया और जिसे उनके राजनितिक जीवन की प्रमुख उपलब्धि माना गया।

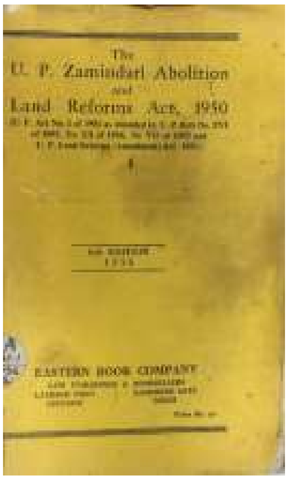

उत्तर प्रदेश ज़मींदरी एवं भूमि सुधार विधेयक पारित कराया, जिसने उन्हें गांवों और किसानों के प्रतिनिधि के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया और जिसे उनके राजनितिक जीवन की प्रमुख उपलब्धि मन गया। इस कानून को गांवों में लिए उन्होंने सारे राज्य के तूफानी दौरे किये, विशेषकर पूर्वी भागों में, जहाँ जमींदारी प्रथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा व्यापक रूप से मौजूद थी और शोषणकारी थी। उन्होंने जेड.ए. एल.आर. के समर्थन में आल इंडिया रेडियो रेडियो पर अनेक भाषण दिए, विभिन्न समाचार-पत्रों में लेख लिखे।

उन्होंने २० मई १९५२ को राजस्व एवं कृषि मंत्री (दो अंतःसम्बद्ध एवं महत्वपूर्ण मंत्रालय) नियुक्त किया गया। २७ दिसंबर १९५४ तक उन्होंने इस मंत्रालय का दायित्व सम्हाला।

राज्य में राजस्व विभाग में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी पटवारियों ने अपनी सेवा शर्तों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए, ज़मींदारों के प्रच्छन्न समर्थन से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। चरण सिंह ने उनकी बाध्यकारी मांगों को मानाने से इंकार कर दिया और सभी २७००० पटवारियों की सेवाएं समाप्त कर त्वरित कार्यवाही करने वाले एवं सख्त प्रशासनिक क्षमताओं वाले नेता की छवि स्थापित की। उन्होंने पटवारियों की जगह लेखपालों का पद सृजित किया, जो चुनी हुई ग्राम सभाओं के प्रति जवाबदेह थे और १८% पदों पर अनुसूचित जाती के लोगों की नियुक्ति के निर्देश दिया। यद्यपि वांछित शिक्षित अभ्यार्थियों के अभाव में अनुसूचित जाती से मात्र ५% ही लेखपाल भर्ती किये जा सके।

"आन्दोलनकारियों की राय थी कि यदि वे अपनी मांगों पर डटे रहे तो एक दिन जीत उनकी ही होगी। ऐसे हालात में, सही रुख, जो सरकार को अपनाना चाहिए, वह यह है कि यदि उसके कर्मचारियों की मांगें या हमारे समाज के किसी भी हिस्से.......... उचित है, सरकार के संज्ञान में लेन पर उन्हें शीघ्रतिशीघ्र स्वीकार कर लिया जाये। यदि मांगें अनुचित हैं, उन्हें कतई नहीं मन जायेगा....... हड़ताल, सत्याग्रह या आन्दोलन के किसी तौर-तरीके के बावजूद....... नेतृत्व के बिना लोकतंत्र अराजकता है" राज्य कर्मचारियों के आंदोलन के मुद्दे पर २१ अप्रैल १९६७ को चरण सिंह की टिप्पणी।

१९५३

उत्तर प्रदेश विधानसभा में "उ. प्र. चकबंदी अधिनियम –१९५३" पारित कराने में मार्गदर्शन किया

उत्तर प्रदेश विधानसभा में "उ. प्र. चकबंदी अधिनियम -१९५३" पारित करने में मार्ग दर्शन किया और १९५४ से इसे सफलतापूर्वक लागू कराया। उन्होंने उर्वरकों को बिक्री-कर से मुक्त किया और बड़े किसानों से सीलिंग में प्राप्त भूमि को अनुसूचित जाति के लोगों में पुनर्वितरण के लिए एक नीति तैयार की। उन्होंने उन किसानों को, जो साढ़े तीन एकड़ तक की जोत के मालिक थे, लगान में भी छूट दी। उन्होंने पशुओं की बिक्री एवं खरीद को विनियमित करने सम्बन्धी, देश में अपनी तरह का पहला, विधेयक तैयार किया, यद्यपि जी.बी. पंत के दिल्ली चले जाने के चलते यह पारित न हो सका।

१९५४

जी. बी. पंत के दिल्ली जाने के बाद डॉ. सम्पूर्णानन्द के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रि पद जारी

जी.बी. पंत का २७ दिसंबर १९५४ को केन्द्रीय गृहमंत्री के रूप में दिल्ली प्रस्थान। "पंत जी के केंद्र में जाने के बाद, चरण सिंह ने दोनों सम्बद्ध मंत्रालयों, साथ ही नीतियों को वांछित दिशा में लागु करने की इस्थिति पर से नियंत्रण खो दिया।" पॉल आर. ब्रास, 'एन. इंडियन पॉलिटिकल लाइफ', वॉल्यूम I , पृष्ठ १२५

२८ दिसंबर को डॉ. सम्पूर्णानन्द की सरकार में उन्हें राजस्व एवं परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया, जहाँ वह ९ अप्रैल १९५७ तक रहे। ज़मींदारों को काश्तकारों से पुनः ज़मीन वापिस लेने की योजना आयोग की अनुशंसा को मानने से इंकार कर दिया, साथ ही कानूनन यह सुधर लागू किया कि कष्टकर के अधिकार में जो ज़मीं है, उसे वापिस नहीं लिया जा सकेगा।

हिन्दू समाज में जाति सोपान क्रम को ध्वस्त करने की दिशा में कदम उठाने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के लिए अंतर्जातीय विवाह अनिवार्य करने हेतु पंडित नेहरू (२२ मई) को लिखा।

१९५६

"व्हीदर को– ऑपरेटिव फार्मिंग" का प्रकाशन

"व्हीदर को- ऑपरेटिव फार्मिंग" का प्रकाशन

१९५७

राजस्व के साथ वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त दायित्व दिया गया

१० अप्रैल १९५७ को राजस्व के साथ वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त दायित्व दिया गया, फरवरी १९५९ में ऊर्जा मंत्रालय का दायित्व भी सौंपा गया।

७७ वर्ष की आयु में पिता मीर सिंह का स्वर्गवास।

१९५८

"एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश" का प्रकाशन

"एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश" का प्रकाशन

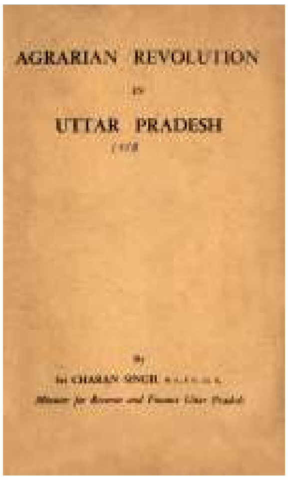

१९५९

जवाहरलाल नेहरू की सामूहिक खेती के प्रस्ताव के विरुद्ध आवाज उठाई, सम्पूर्णानन्द से लगातार गहराते मतभेदों के चलते उ. प्र. मंत्रिमंडल से त्यागपत्र

जनवरी में नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ६४वें अधिवेशन में चरण सिंह ने सहकारी खेती के विरुद्ध एक घंटे लम्बा बेहद सुतार्किक और आक्रामक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सहकारी खेती को एक व्यवस्था के तौर पर, भारतीय स्थितियों के पूरी तरह प्रतिकूल बताया। उनके जोशीले भाषण का जोरदार स्वागत हुआ, किन्तु फिर भी सहकारी कृषि के पक्ष में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। सामूहिक या सहकारी खेती को कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने वाला नेहरूवादी सिद्धांत माना गया, जिसका शक्ति और अधिकार सम्पन्नता के शिखर पर आसीन नेहरू के विरोध का किसी को साहस न हुआ और इसका विरोध करने वाले को 'प्रतिक्रियावादी' माना गया। इसने चरण सिंह को उनके कुछ मतदाताओं के बीच तो लोकप्रिय बना दिया किन्तु उन्हें नेहरू और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निशाने पर ला दिया।

बाद में सोवियत रूस और कम्युनिस्ट चीन में सहकारी खेती की असफलता ने चरण सिंह की दूरदृष्टि और भारतीय किसान के प्रति उनके विचारों को वैधता प्रदान की, जबकि नेहरू के अल्पकालिक जोशीलेपन पर यह गंभीर अभियोग था।

चरण सिंह ने २२ अप्रैल को एक-दूसरे से जुड़े विभिन्न मुद्दों, जो १९५४ और उससे भी पहले से अंदर ही अंदर भदक रहे थे, के चलते सरकार से त्यागपत्र दे दिया ; जिनमें प्रमुख थे-- राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति मोहभंग, सरकारी मशीनरी में बढ़ते भ्रष्टाचार के प्रति निष्फलता, राज्य की राजनीती में शहर और व्यापार के प्रति पक्षपात, मुख्यमंत्री डॉ. सम्पूर्णानन्द की व्यक्तिगत अक्षमता, पूंजीपति साहू जैन एवं बिड़ला के हिंडाल्को से सम्बंधित मुद्दे और फिर राज्य कांग्रेस के अंदर दलगत राजनीति में चरण सिंह का अलग-थलग किया जाना। १९३७ से वह पहली बार, १९ माह के लिए, २२ अप्रैल १९५९ से दिसंबर १९६० तक सरकार से बाहर रहे।

"चरण सिंह ने स्पष्ट किया है कि उनके और सम्पूर्णानन्द के बीच जो मुद्दे हैं, वे देश की समस्याओं के समाधान के आंकलन को लेकर बुनियादी मतभेदों को दर्शाते हैं, क्या इनका समाधान कृषि में सुधार और उत्पादन में वृद्धि में निहित है या औद्योगिक विकास में है.... वह वक्तव्य, जो २१ अगस्त १९५९ को विधान सभा में दिया जाना था किन्तु कभी सामने नहीं आया..... ५२ पृष्ठों का एक अति विशिष्ट दस्तावेज है .... यह स्थितियॉ की निर्मम विवेचना है, बेहद विश्लेषणात्मक, राज्य की विकासवादी नीतियों की आद्यान्त अर्थपूर्ण समीक्षा। इस दौर में

भारत में कहीं भी इस तरह के कुछ ही वक्तव्य होंगे, जो इतनी परिस्कृत, स्पष्टत और समर्पण भाव से लिखे गये होंगे।" पॉल आर. ब्रास (२०११) एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ, वॉल्यूम, पृष्ठ १४९-१५०

१९५९

"ज्वाइंट फार्मिंग एक्स–रेड : समस्या और इसका समाधान" का प्रकाशन

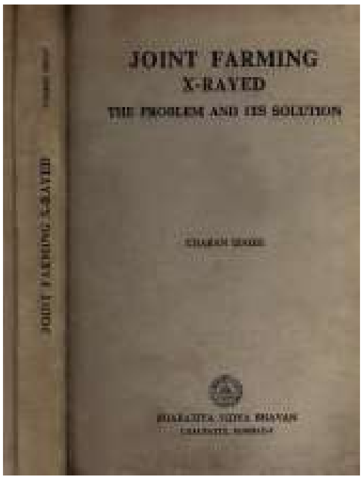

हमारे अर्थशास्त्रियों एवं योजनाकारों ने भारतीय परिस्थितियों का जायजा नहीं लिया क्योंकि वे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से प्रभावित थे और कार्ल मार्क्स ने विना इस तथ्य का परिक्षण किये कि जो नियम औद्योगिक विकास पर लागु हैं वही कृषि पर भी लागु हैं, अपने सिद्धांत को अंतिम हैं। भारत में जोतने योग्य भूमि सिमित हैं जबकि जनसँख्या का घनत्व अधिक। अतः प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि जरुरी है। अमेरिका, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया और कई अन्य उन जैसे मुल्कों में जहाँ भूमि प्रचुर मात्र में एवं श्रमिक अल्प संख्या में उपलब्ध हैं, वहां बड़ी मशीनों के प्रयोग से खेती द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ता हैं।

पेट्रोल और डीजल के प्रयोग से विस्थापित मानव एवं पशु शक्ति का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता हैं। बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारे देश की परिस्थितियों के मद्देनजर, बड़ी-बड़ी जोतों के कारन खेती से अलग हुए किसानों की भारी तादात को खपाने में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र अपर्याप्त होगा। अतएव सहकारी खेती को राष्ट्रीय निति का अंग मानने में महत्वपूर्ण मानवीय पक्ष की उपेक्षा निहित है। आयातित मशीनरी एवं गतिशील ऊर्जा का प्रयोग देश में उपलब्ध अपर्याप्त मुद्रा विनिमय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसका अंदाजा नहीं लगाया गया कि बैल के स्थान पर ट्रेक्टर का प्रयोग करने से खेती के लिए गोबर खाद अत्यन्त काम हो जाएगी और फिर भरपाई के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ाना होगा। इस पुस्तक में समाहित साक्ष सिद्ध करेंगे कि अकार्बनिक खाद का प्रयोग तुरंत परिणाम तो देता है परन्तु धीरे-धीरे मिट्टी की उर्वरा-शक्ति का भी क्षरण करता हैं, दूसरी तरफ कार्बनिक खाद, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के साथ ही खाद्य पूर्ति के स्रोत के रूप में भूमि को अक्षुण्ण रखता हैं. अतएव कृषि की बेहतरी के लिए अब इस देश के कृषि विशेषज्ञ शुद्ध सिंथेटिक सलफेट्स एवं फास्फोरस का प्रयोग करने का परामर्श नहीं देते हैं। देश में जदबजी में किया गया उपक्रम ऐसा न हो की बाद में आज के नेताओं की निंदा का कारन बने।

संक्षेप में स्थापित लोकतंत्रिक सिद्धांतों को आहत करेगी, नौकरशाही का निमन्त्रण आमंत्रित होगा और दुष्परिणामों वाला मशीनीकरण तीव्र होगा। दूसरी तरफ खेती-किसानी देश के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करेगी, जो शानदार भले न हो परन्तु उसमें अचानक पटरी से उखड़ने के अवसर भी नहीं आएगा।

वस्तुतः, हमारी समस्याएं लड़खड़ा देने वाली हैं। यदि हम उनका अनुमान लगाएं। हमारा सामना अत्यन्त पूंजीगत भरी अवरोध से हैं, जनसँख्या-वृद्धि के अनुपात में पूंजी निर्माण अत्यन्त कम अनुपात में है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हैं, उससे भी अधिक अल्परोजगारी हैं, सापेक्षित रूप से अपर्याप्त भूमि एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत हैं, अपर्याप्त कृषि उत्पादन हैं और एक ऐसी अधीर जनसँख्या हैं, जिसकी अपेक्षाएं जाग्रत हैं और जिसे आर्थिक असमानताओं एवं बढ़ती गरीबी का पूरा बोध हैं। इन समस्याओं से निपटने से लिए हमारी सारी ऊर्जा, कौशल, प्रशासन क्षमता और राजनैतिक क्षमताओं का उपयोग जरुरी होगा।

ऐसा कोई उदहारण प्रस्तुत नहीं हैं, जिसका अनुसरण भारत अपनी समस्याओं के समाधान में कर सके, क्योंकि किसी भी अन्य मुल्क की परिस्थितियॉ हमारे जैसी नहीं हैं। हम कभी अमेरिका के मानकों को नहीं अपना सकते क्योंकि प्रति व्यक्ति भौतिक स्रोत तुलनात्मक रूप से अत्यल्प हैं, या इंग्लैण्ड के मानक भी नहीं अपनाए जा सकते क्योंकि जैसा शोषण विदेशी स्रोतों और लोगों के बल पर करते हुए उन्होंने औद्योगिक ढांचा तैयार किया हैं,

वैसा निर्माण हम नहीं कर सकते। यही नहीं, हम सोवियत रूस या चीन के तौर-तरीकों को भी नहीं अपना सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक स्रोत-व्यक्तियों का अनुपात रूस के पक्ष में हैं तथा कुल मिलाकर लेन- देन का चिट्ठा दोनों देशों के पक्ष में हैं और इसके अलावा इसलिए भी क्योंकि हमने लोकतजंत्रिक संविधान का रास्ता चुन है।

यह सोच कि अधिक जनसँख्या वृहत औद्योगीकरण के लिए अपने आप में एक पूंजी हैं, एक अल्पकालिक सोच हैं। जनसँख्या के अनुपात में प्राकृतिक स्रोत की कमी के सन्दर्भ में, हमारी काम क्रयशक्ति और यह मान लेना कि भौतिक स्रोतों से अंततः पूंजी या वित्तीय स्रोत का निर्माण कर लिया जायेगा, के बावजूद भारत की भारी जनसँख्या आर्थिक विकास या औदोगीकरन के रस्ते में अवरोध हैं, जिसमे उक्त सब कारक पूंजी निर्माण के न होकर 'दायित्व' वृद्धि के ही होंगे।

हालाँकि, उक्त सबके प्रति मात्र नकारात्मक रुख अख्तियार करना ठीक नहीं होगा। तदैव पुस्तक में इन बताऊँ पर सकारात्मक उत्तर देने का भी प्रयास किया हैं।

"नवीन खोजों को बढ़ावा देना या तकनीकी सुधार उतना ही आवश्यक हैं जितना पूंजी निर्माण। केवल तीन सौ वर्ष पूर्व, भारत आर्थिक स्टार के कम से कम स्तर, जिस पर पश्चिमी यूरोप था। आज स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। पश्चिम वालों का नवीन खोजों को बढ़ावा देने की प्रवृति इसका कारण हैं। वहां पहुँचने के लिए निरक्षरता, अस्वस्थता, जातीय व्यवस्था और जीवन की भाग्यवादी धारणाओं, जिससे अधिकांश ग्रस्त हैं, जैसे अवरोधों को समाप्त करना होगा। तभी उपलब्ध पूँजी और श्रम दोनों की प्रभावोत्पादक दक्षता में सुधर होगा।

तकनीकी सुधार पर भी मुख्य बल देना होगा, उदाहरण के लिए स्वदेशी हल में, कार्बनिक खाद के उपयोग में, लघु सिंचाई कार्यों में और लघु उद्योगों एवं हस्तकला के संगठन में तकनीकी सुधार पर जोर जरुरी है न कि बड़े पैमाने पर महंगे यूरोपियन व अमेरिकी मॉडलों जैसे बड़े फार्म, बड़े कारखाने, बड़ी सिंचाई या पनबिजली परियोजनाओं पर कार्य किया जाये। इन बातों के आलावा, बड़ी आर्थिक परियोजनाएं परिणाम देने में काफी वक्त लेती हैं। पूंजी प्रवाह भी काफी समय के लिए रुक जाता हैं और इस बीच , समय की अंतरात्मा एवं जनसँख्या में वृद्धि के कारण समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं तथा और अधिक प्रचण्ड रूप धारण कर लेती हैं।"

अन्यथा, यह बातें कहीं न कहीं वर्णित हैं, शायद इससे भी बेहतर रूप में। विचार और शब्दों दोनों में मैंने, डेविड मित्रांनी की पुस्तक 'मार्क्स अगेंस्ट द पीजेंट' (George Weidenfield and Nicolson Ltd., London, 1951), होरेस बेलशा की पुस्तक 'Population Growth and Levels of Consumption (George Allen and Unwin Ltd., London, 1956) Elmer Pendell's Population on the Loose (New York, 1951) and Kingsley Davis's Population of India and Pakistan (Princeton University Press, New York, 1951). से प्रेरणा प्राप्त की हैं। इन पुस्तकों के लेखकों का ऋणी हूँ एवं आभार प्रकट करता हूँ।"

१९६०

मुख्यमंत्री सी.बी. गुप्ता के मंत्रिमंडल में शामिल।

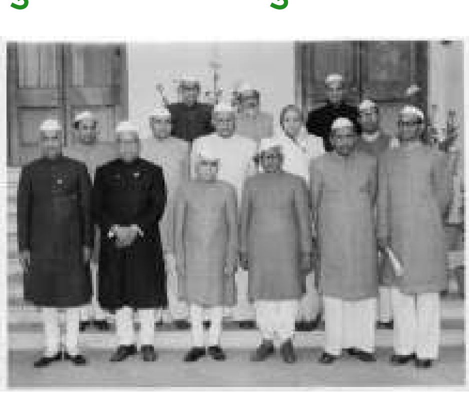

७ दिसम्बर को बतौर गृह एवं कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सी.बी. गुप्ता के मंत्रिमंडल में शामिल। मुख्यमंत्री से मतभेदों के चलते, १३ मार्च १९६२ को गृह विभाग वापस ले लिया। कृषिमंत्री के पद पर १ अक्टूबर १९६३ तक कार्यरत रहे। उ.प्र. विधानसभा द्वारा भू-जोतों पर हदबंदी अधिनियम- १९६० का पारित होना, जिसमें उन्होंने प्रबल रुचि ली।

" (चरण सिंह) ..... कहते हैं कि कृषि मंत्रालय एक अत्यन्त कटा-छटा विभाग है, कतर - ब्योंत की प्रक्रिया पंत जी के समय में ही आरम्भ हो गई थी और सम्पूर्णानन्द एवं गुप्ता दोनों के शासनकाल में जारी रही।"

- २१ अप्रैल १९६२ को लखनऊ में पॉल ब्रास के साथ साक्षात्कार में।

माँ नेत्र कौर ७५ वर्ष की आयु में चल बसीं।

गुरु एवं पिता तुल्य गोविन्द बल्लभ पंत का ७ मार्च १९६१ को निधन।

२ अक्टूबर १९६३

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी मंत्रिमंडल में शामिल

सुचेता कृपलानी मंत्रिमंडल में २ अक्टूबर १९६३ को कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन मंत्री के रूप में शामिल। उन्होंने "उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम १९६३" तैयार किया।

१९६४

कृषक समज की स्थापना।

U.P. Minister rules out State trading in grains

From our Special Correspondent

Lucknow, Aug. 5—Agriculture Minister Charan Singh said today that the State trading in food grains was a colossal undertaking, impracticable in the present circumstances.

[illegible]

कृषि में आधुनिक वैज्ञानिक तौर-तरीकों /उपायों के जरिये छोटे एवं साधारण किसानों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कृषक समाज की स्थापना।

२७ मई १९६४ को जवाहरलाल नेहरू का निधन।

एक समय उत्तर प्रदेश में ११ जनवरी १९६६ तक साथ-साथ संसदीय सचिव रहे लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री चुने गए।

१९६४

इण्डिया'ज पॉवर्टी एण्ड इट्स सॉल्यूशन का प्रकाशन

इण्डिया'ज पॉवर्टी एण्ड इट्स सॉल्यूशन का प्रकाशन

१४ मई १९६५

कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मतभेद ज़ारी ।

Charan Singh wants change in portfolio

Lucknow, May 13 (PTI)—Uttar Pradesh Agriculture Minister Charan Singh has in a letter to Chief Minister Sucheta Kripalani requested her to relieve him of his agriculture portfolio, according to sources close to the Chief Minister.

The sources said before the commencement of the last budget session Mr Singh had communicated to the Chief Minister that if he was to retain agriculture portfolio he should also have allied portfolios like irrigation and community development, otherwise he would press her for permission to retain only the forest portfolio.

In view of his insistence on the change of portfolio, a reshuffle of portfolios of the ministers in the Cabinet may soon be effected.

१४ मई को कृषि मंत्रालय वापिस ले लिया गया। वन एवं स्थानीय निकाय मंत्रालय में १४ फरवरी १९६६ से १३ मार्च १९६७ तक रहे। यद्यपि जब स्थानीय निकाय जैसा साधारण मंत्रालय सम्हाल रहे थे, तब भी उन्होंने प्रशासन में अपने सिद्धांतों को लागू करना जारी रखा।

वास्तव में, उनके दिमाग में यह बात थी कि , "कुछ उच्च पदस्थ भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसा उदाहरण बनाया जाये जिसके चलते पूरे राज्य के स्थानिक निकायों के सेवक सावधान हो जायें। " ..... आज, लोकजीवन का स्तर काफी गिर गया है। वस्तुतः कोई भी मानक, जिसे नाम दिया जा सके, अब नहीं बचा है। बजाय इसके कि इन्हें लोकसेवा का अवसर माना जाता। अब अधिकांश लोगों की राय में लोक दायित्व के कार्यालय लाभ एवं स्वयं की उन्नति के स्रोत हैं। यदि यह स्थिति विना किसी रोकथाम के जारी रहती हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य असाध्य रूप से गर्त में चला जायेगा। इस बात से हताश होने की अपेक्षा कि लोक-जीवन की स्थितियों में वृद्धि एक विशेष आकार लेती जा रही है, में विना किसी हिचकिचाहट के, कार्यवाही हेतु प्रस्तावित करता हूँ........" १९६६ में मेरठ म्युनिसिपल बोर्ड के एक सदस्य को निलम्बित करने पर। पॉल आर. ब्रास (२०११) एक भारतीय राजनैतिक जीवन, वॉल्यूम १, पृष्ठ १४९-१५०।

और निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही ऊँचे वेतन व महंगाई भत्ते के लिए किये जा रहे आंदोलनों पर उनकी राय।

"यदि जाँच कराई जाये तो ज्ञात होता है कि देश भर के सरकारी सेवकों को मिलने वाले परिलाभों की कुल धनराशि की भूमिका, आज के आर्थिक संकट को पैदा करने में कम नहीं रही है, जिसका हम दैनंदिन रूप में सामना करते हैं। सरकारी सेवक (संगठित श्रमिक वर्ग के साथ) उस साधन-सम्पन्न समाज से आते हैं, जो आमजन से पूरे तौर पर कट हुआ है। इस वर्ग के परिलाभों का उन लोगों की प्रति व्यक्ति आय से कोई संबन्ध नहीं है, जिनकी सेवा में वह कार्यरत है। दोनों के, अर्थात एक मालिक के और नौकर के जीवन में परस्पर कोई साम्य या संवाद नहीं हैं। " उ.प्र. राज्य कर्मचारियों के आंदोलन पर ३० जून १९६६ को सुचेता कृपलानी के लिखे गए कैबिनेट नोट से उदधृत।

"कुछ प्रश्न विचार के अंतर्गत आते हैं कि क्या हमारे आम जनों की औसत आय का लोकसेवकों को मिलने वाले परिलाभों से सीधा सम्बन्ध होना चाहिए अथवा नहीं। क्या केवल सरकारी सेवकों की आवश्यकतायें ही विचारणीय होनी चाहिए और उन लोगों की नहीं जिनकी जेबों से अंततः ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति-आपूर्ति होती है। जब मूल्य वृद्धि या महंगाई में बढ़ोत्तरी होती है तब क्या तुलनात्मक रूप से अल्प आय भोगी कर्मचारी अधिक वित्तीय सहायता पाने का अधिकारी है अथवा बेहतर वेतनभोगी कर्मचारी ? क्या उच्च वेतनभोगी

अधिकारियों को कोई महंगाई-भत्ता दिया जाना चाहिए? कुल मिलाकर हमारे आम लोगों की आय और लोकसेवकों की आय के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है।" [उ.प्र. राज्य कर्मचारियों के आंदोलन पर २७ जुलाई १९६६ को इंदिरा गांधी को लिखे पत्र से उदधृत]।

"जब से आज़ादी मिली है तब से सारा जोर भत्तों के अधिकार, लाभों, श्रमिक वर्ग की सुविधा-रियायतों इत्यादि देने पर है, जबकि कठोर श्रम अथवा कर्तव्य का निर्वहन जो आज दुर्लभ गुण बन गए हैं, के बारे में कोई बात नहीं करता हैं। पश्चिम के मुकाबले भारत में कारखानों के श्रमिक उत्पादन कम करते हैं और पते ज्यादा हैं। विणा किसी संशय के कहा जा सकता हैं की यह देश में विद्यमान आर्थिक रुग्णता के कारणों में से इस है। " १८ अगस्त १९६६ को चरण सिंह द्वारा टी.न. सिंह, केंद्रीय इस्पात मंत्री को लिखे गए पत्र से उदधृत।

१९६७

३८ वर्ष बाद, कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

इंदिरा गांधी से समझौता-वार्ता असफल हो जाने पर इसे विश्वासघात बताते हुए १ अप्रैल को १७ विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी । यह अनेक दृष्टांतों में पहली घटना है, जब चरण सिंह के राजनैतिक रस्ते इंदिरा गांधी के रास्तों से टकराए और वे इनमें जीते हों, वरना अधिकांशतः इंदिरा गांधी अपनी कूटनीति के चलते उन्हें पराजित करती आई हैं।" (पॉल ब्रास)

अनेक विपक्षी दलों को मिला कर बने संयुक्त विधायक दल के चरण सिंह सर्व सम्मति से नेता चुने गए। उत्तर प्रदेश के प्रथम गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री पद पर ३ अप्रैल १९६७ से २५ फरवरी १९६८ तक आरूढ़ रहे; और एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का आरम्भ किया, जिसने तथाकथित अन्य पिछड़ी जातियों (ओ.बी.सी.) का एक प्रभावी शक्ति के रूप में उभरना तय कर दिया।

१९६७ के लोकसभा चुनावों के बाद, कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक अखिल भारतीय पार्टी बनने पर हुमायूँ कबीर की पहल पर ९ अप्रैल को नई दिल्ली में गैर-कॉग्रेसी मुख्यमंत्रियों एवं अन्य महत्वपूर्ण नेताओं की एक बैठक बुलाई गई। सभी उपस्थित नेता सैद्धांतिक रूप से अखिल भारतीय पार्टी बनाने पर एकमत हुए और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने सभी गैर शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न राज्यों के विचारधारा वाली पार्टियों के अध्यक्षों एवं महासचिवों को मई १९६७ में पटना में आयोजित होने वाली बैठक में आमंत्रित किया। इस बैठक में एक नए दल - भारतीय क्रांति दल दल के गठन का निर्णय लिया गया और महामाया प्रसाद सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए। चरण सिंह इसकी कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। बाद में उन्होंने अपनी जन कांग्रेस पार्टी को बी.के.डी. में विलय कर दिया और दल के अध्यक्ष पद को ग्रहण किया, जो समय के साथ उत्तर प्रदेश में अधिक जनाधार वाला दाल बना।

"भ्रष्टाचार पेचीदगी की हद तक बढ़ गया था। मैं इसके लिए राजनीतिज्ञों को जिम्मेदार था न की नौकरशाही को। मेरा अनुभव कहता है की अधिकारियों के व्यवहार को राजनैतिक नेतृत्व परिभाषित करता है, वे उन्हीं के दिशा-निर्देशों पर कार्य करते हैं। यह ऐसा है जैसे कि घोड़े और उसके सवार के बीच का सम्बंध। घोड़ा बड़ी जल्दी समझ जाता है कि पीठ पर चढ़ा वाहक घुड़सवारी जानता भी हैं कि नहीं और तुरंत उसे गिरा देता है, यदि वह समझ जाता है कि घुड़सवार अनाड़ी है । .... भ्रष्टाचार ऊपर से आरम्भ होता है, न कि नीचे से। (नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी ओरल हिस्ट्री परियोजना के श्यामलाल मनचंदा को लखनऊ, उ.प्र. में १० फ़रवरी १९७२ को दिए गए साक्षात्कार से)।

१९६९

जनसंघ, सोशलिस्ट और कांग्रेस की अपेक्षा भारतीय क्रांति दल (बी.के.डी.) का उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया ढंग से काम करना। यही तीनों दल अगले १६ वर्ष तक इनके राजनैतिक विरोधी और मित्र भी रहे।

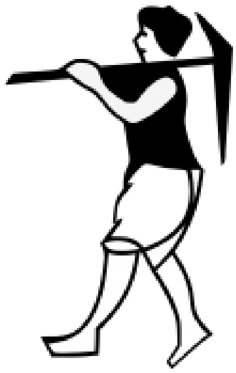

एक वर्ष के राष्टपति शासन के बाद तक उत्तर प्रदेश में फ़रवरी में मध्यावधि चुनाव शुरू हुए, जिसमें जन कांग्रेस के दौरान चरण सिंह की बी.के.डी. पार्टी के १७ विधायकों की संख्या बढ़कर ९८ हो गई। अधिकांशतः यह सीटें उनके संयुक्त दल के घटकों, विशेषकर जनसंघ की कीमत पर आई, जिसकी सीटें घटकर आधी अर्थात ९८ की तुलना में मात्र ४९ रह गई और साथ ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सीटें भी ४४ से घटकर मात्र ३३ रह गईं। इससे भविष्य में, विशेष रूप से जनता दल के शासन में, उनके जनसंघ से जारी तनावों का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह सब कुछ हुआ विना किसी संगठित धन व्यवस्था के अथवा बी.के.डी. में विना किसी नामधारी सांगठनिक ढांचे के चलते। और चरण सिंह की यही विशेषता उनकी बाद में बनने वाली सारी राजनैतिक पार्टियों के सम्बंध में विद्यमान रही। उन्होंने कभी भी धनी व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों से धन की आकांक्षा नहीं की और सदैव जन सभाओं में इकट्ठा होने वाले धन पर निर्भर रहे।

जनसंघ ने उनकी सत्ता-अस्तित्व सी शक्ति को हमेशा अपने राजनैतिक आधार के लिए खतरा महसूस किया और वे १९८५ तक सीमित सन्दर्भों में कभी उनके मुकाबले में तो कभी उनके सहयोगी रहे।

१७ फ़रवरी १९७०

कांग्रेस की सहायता से दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

उत्तर प्रदेश में सत्ता सम्भालने के लिए कांग्रेस के दोनों घटकों द्वारा समर्थन के प्रस्ताव के मद्देनजर इंदिरा गांधी की कांग्रेस (आर) की सहायता से चरण सिंह उत्तर प्रदेश में १७ फरवरी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तथा २९ सितंबर तक बने रहे। चरण सिंह द्वारा बी.के.डी. को कांग्रेस आर. में विलय से मना कर देने पर दोनों दलों के बीच समझौता टूट गया। और इस टूट का एक कारण यह भी रहा की राज्यसभा में उनकी पार्टी के तीन सदस्यों ने भारतीय राजाओं के प्रिविपर्सों को समाप्त करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी द्वारा लए गए प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया।

भ्रष्टाचार के आरोप पर, २८ अप्रैल को सभी ५१ जिला परिषदों को भंग कर दिया।

सक्सेना, एन. एस. (१९९३) इंदिरा : टूवर्ड्स एनार्की १९६७-१९९२, अभिनव प्रकाशन, दिल्ली। वरिष्ठ आई.पी. एस., प्रमुख- सी.आर.पी. एफ., सदस्य - यू.पी. एस. सी., सदस्य- नेशनल पुलिस कमीशन।

"श्री चरण सिंह ....साम्प्रदायिक दंगों के लिए कुख्यात उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे दंगों को शून्य कर देने का जादुई कार्य किया.... ऐसा देश की कानून व्यवस्था को लागू करके किया। कोई भी गलत इरादे से एक पत्थर भी फेंकता तो उसे गिरफ्तार किया जाता, उस पर मुकदमा चलाया जाता और अभियोजन सिद्ध होने पर विना किसी छूट के और विना तथाकथित राजनैतिक बंदियों के लिए उच्च श्रेणी का ख्याल किये जेल भेज दिया जात पृष्ठ २८.

"मुझे उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के बारे में चरण सिंह के रुख कोजानने के तीन अवसर यथा दिसंबर ७, १९६० से फरवरी १९६२ के मध्य, जब वे उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री थे, अप्रैल १९६७ से फरवरी १९६८ के बीच जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और फरवरी १७, १९७० से अक्टूबर २, १९७० के दौरान जब वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, प्राप्त हुए। पहले अवसर पर जब मैं मेरठ परिक्षेत्र, जो चरण सिंह का गृह क्षेत्र भी था, का डी. आई. जी. था। तीसरे अवसर पर मैं उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख था। सभी तीनों अवसरों पर कानून का उल्लंघन करने वालों को चरण सिंह ने कोई रियायत नहीं दी। उस समय अखबार कुछ अथवा इतर कारणों से चरण सिंह के प्रति प्रतिकूल नजरिया अपनाए हुए थे और जनता के किसी भी वर्ग के विरुद्ध कानून व्यवस्था के उल्लंघन में संलग्न जाटों के उपद्रवी के बारे में बड़े-बड़े अक्षरों में शीर्षक लगाकर ख़बरें छपते, विशेष रूप से हरिजनों से सम्बंधित खबरों को। यदि ऐसा कोई सच या खबर चरण सिंह के संज्ञान में आती तो वे पुलिस को तब तक चैन नहीं लेने देते जब तक अपराधी विना जमानत के जेल में न डाल दिए जाते। .... मुझे कोई शंका नहीं है की यदि चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते तो कानून व्यवस्था के विरुद्ध उकसाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत या तो चुप हो जाते या फिर जेल में होते। चरण सिंह की यही घोषित नीति थी की ऐसे बंदियों को कभी भी जेलों में उच्च श्रेणी न दी जाये। " पृष्ठ ५२-५३।

"१९७० के शुरुआती दौर में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख था और चरण सिंह मुख्यमंत्री। उनके कुछ अनुयायियों, जो नियमों को नहीं मानते थे, जिनमें राजनारायण प्रमुख थे, द्वारा प्रधानमंत्री की बैठक को बाधित करने की धमकी दी गई। मुख्यमंत्री ने हमें उनके ऐसे किसी भी अनुयायी को गिरफ्तार करने की स्पष्ट स्वतंत्रता दी, यदि वे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बाधक बनते हैं। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कार्य आसान हो गया। " पृष्ठ १२६

"उत्तर प्रदेश पब्लिकमैन इन्क्वायरीज ऑर्डीनेंस १९६७, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सर्वोत्तम अधिनियम है और इसका अधिनियमन चरण सिंह द्वारा किया गया था, जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। .... इस सन्दर्भ में सबसे सही अभिमत यही था जो चरण सिंह ने अपने सार्वजनिक भाषण में कहा कि यदि गृहमंत्री स्वयं भ्रष्ट है तो वह एक अपराधी मोटर चालक से रिश्वत लेते ट्रैफिक कॉन्स्टेबल पर कैसे ऊंगली उठा सकता है ?" पृष्ठ १७९

१४ नवंबर १९७०

"नई कांग्रेस–बी.के.डी. रिश्तों की कहानी – नई कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन कैसे तोड़ा"

नई कांग्रेस-बी.के.डी. सम्बंधों की कहानी का प्रकाशन, उत्तर प्रदेश में नई कांग्रेस ने गठबंधन कैसे तोड़ा

१९७१

इंदिरा गांधी ने मार्च में लोकसभा चुनावों की घोषणा की। चरण सिंह मुज़फ्फरनगर से पहला लोकसभा चुनाव हारे

इंदिरा गांधी ने मार्च में लोकसभा चुनावों की घोषणा की और "गरीबी हटाओ" के लोकलुभावन नारे से विशाल (५४२ में से ३५२ सीटें जीत कर) बहुमत हासिल किया।

चरण सिंह लोकसभा का पहला चुनाव मुज़फ्फरनगर से हार गए। उ. प्र. विधानसभा में नेता विरोधी दल के रूप में १९७७ तक लखनऊ में रहे।

१९७४

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में बी.के.डी. ने अच्छा प्रदर्शन किया किन्तु बिखरे विपक्ष के कारण कांग्रेस के प्रभुत्व को समाप्त न कर सकी। कांग्रेस के विरोधी दलों को अपने नेतृत्व में एक साथ लाने के प्रयास जारी रहे, भारतीय लोक दल का गठन।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव १९७४ में आयोजित हुए, जिसमें बी.के.डी., एस. एस. पी. और मुस्लिम मजलिस ने चरण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की २१५ सीटों के मुकाबले १०६ सीटें जीतीं। सरकार पर बड़े पैमाने पर मतदान में बल प्रयोग और धांधली के आरोप लगे। यह माना गया की विपक्ष के बीच च वोटों के विभाजन के चलते कांग्रेस अल्पमत (३२%) से जीती है, जबकि बी.के.डी. २१%, जनसंघ १७%, कांग्रेस (ओ) ८% और समाजवादियों ने ३% वोट हासिल किये।

संयुक्त विधायक दल (एस. वी. डी.) के अपने तजुर्बे से सीख लेते हुए, जहाँ आसमान विचारों वाला गठबंधन विरोधाभाषी दिशाओं में भटक गया था, उन्होंने एक सर्वसम्मत पार्टी संविधान, झंडा, चुनाव चिन्ह और नेतृत्व के आधार पर विपक्षी एकता कायम करने के लिए एक गम्भीर प्रयास किया। उनके इन प्रयासों को कांग्रेस (ओ) और जनसंघ ने धक्का पहुंचाया। इन दोनों पार्टियों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने को प्रमुखता दी। फिर भी कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प देने की दिशा में पहले कदम के रूप में उन्होंने बी.के.डी., स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उत्कल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक दाल, किसान मजदूर पार्टी और पंजाबी खेती-बाड़ी जमींदारी यूनियन का विलय कर २९ अगस्त को भारतीय लोक दल (बी.एल.डी.) की स्थापना की।

जून १९७५ - मार्च १९७६

इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान चौथी बार जेल गये, स्वतंत्र भारत में पहली बार

इंदिरा गांधी के अधिनायकवादी आपातकाल में २५ जून' ७५ से मार्च १९७६ तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहे। जेल से रिहा होने पर आपातकाल की भर्त्सना करता हुआ और इंदिरा गांधी के विरोध को सबल बनाता २३ मार्च १९७६ को यू. पी. विधानसभा में चार घंटे तक ऐतिहासिक भाषण दिया। विपक्षी एकता कायम करने के प्रयास उन्होंने दुगुने कर दिए किन्तु मोरारजी देसाई की नेता बनने और जनसंघ को एक अलग राजनीतिक दल के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने की आकांक्षा जैसे मुद्दों का उन्हें सामना करना पड़ा।

१९७७

जनता पार्टी की स्थापना में सहयोग, और चुनावों में उत्तर भारत में कांग्रेस को हराने के लिए प्रमुख चुनावी रणनीतिकार रहे। केंद्रीय गृह मंत्री बने।

इंदिरा गांधी ने २८ मार्च को एक महीने में चुनावों की घोषणा कर दी और आपातकाल का लौह-आवरण इस उम्मीद के साथ उठा लिया की विपक्ष आपस में झगड़ना जारी रखेगा और चुनाव में उतरने को तैयार नहीं होगा। उन्होंने गलत आंकलन किया- विरोधी दलों ने उन्हें एवं खुद को आश्चर्य में डाल दिया और जनता पार्टी का गठन किया।

चरण सिंह ने १९७७ के आम चुनावों में कांग्रेस की हार का प्रमुख चुनावी आधार प्रदान कर दिया था, जनता पार्टी में ही बी.एल.डी. घटक से ही सौ सांसद आ गए (अन्य घटक थे भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ) और केंद्रीय सी.एफ.डी.) ७५ वर्ष की आयु में सांसद चुने गए तथा केन्द्रीय गृह मंत्री बने और २४ मार्च १९७७ से १ जुलाई १९७८ तक इस पद पर बने रहे। वह अक्सर कहा करते थे कि किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिहाज से वह १० वर्ष से भी अधिक विलम्ब से संसद में पहुंचे हैं।

१९७८

इंडिया'ज इकोनॉमिक पॉलिसी : दि गांधियन ब्लू प्रिंट" का प्रकाशन।

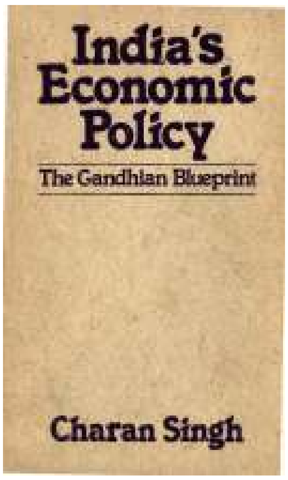

इंडिया'ज इकोनॉमिक पॉलिसी : दि गांधियन ब्लू प्रिंट" का प्रकाशन।

यदि हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, तो केवल दो तरीके हैं : पहला, उत्पादकता में प्रति एकड़ वृद्धि और साथ ही साथ प्रति एकड़ श्रमिकों की संख्या में कमी; दूसरा, अपने इस राष्ट्रीय मनोविज्ञान, विशेषकर हिन्दुओं का, रूपांतरण करना होगा कि जगत मिथ्या है। व्यक्तिगत रूप से और एक राष्ट्र के रूप में भी हम विकसित हों और अपने आर्थिक हालात के सुधार पर जोर दें; और इस तरह हमारी जनता काम को बेहतर तरीके से और परिश्रम से करना सीखे.....पृष्ठ ३

.... वृहद् अर्थों में कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के सम्पूरक हैं, यह मामला बलाघात और प्राथमिकताओं का है .... यद्यपि इस सबका अर्थ यह नहीं है कि उद्योग उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कृषि। यह कृषि ही है] जो आधारभूत भूमिका निभाती है - एक अग्रदूत की।

...... अतः जब तक कि यह देश आर्थिक विकास के मौजूदा ढांचे से प्रतिबद्ध रहता है, जिसमें कि केवल शहरी अभिजात्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए या उनके उत्पादों को बेहद कम मूल्य पर निर्यात करने के लिए भारी लागत पर पूंजी बहुल आधुनिक उद्योग कायम करना शामिल है। इससे न केवल बेरोजगारी में वृद्धि होगी और पूंजी कुछ ही हाथों में केंद्रित होकर रह जाएगी बल्कि इससे धनी देशों की गुलामी का खतरा भी गहरा और गहरा होता जायेगा। इस खतरे से बचने का एकमात्र सही रास्ता, दूसरे शब्दों में आर्थिक एवं तकनीकी तौर पर आत्मनिर्भर बनने का औद्योगीकरण के मौजूदा ढांचे को तोड़ दिया जाये और बदलाव लाने या हालत को बदलने के लिए गांधीवाद का रास्ता अपनाया जाये। पृष्ठ ११५

१९७८

जनता पार्टी के बीच उभरे मतभेद, कांग्रेस (ओ), जनसंघ, बी. एल. डी., सी.एफ.डी. घटकों के बीच अंतर्कलह

इंदिरा गांधी पर अभियोग चलाये जाने के तौर-तरीके को लेकर उभरे मतभेदों के कारण जुलाई में मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाल दिए गए। असली कारण था सत्ता : कांग्रेस (ओ) और जनसंघ ने चरण सिंह के प्रमुख सहयोगियों को उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में तथा पार्टी की केन्द्रीय राजनीतिक इकाइयों में निष्प्रभावी बनाने की योजनाएं बनाईं । उनके सामने कोई और रास्ता न बचा था सिवाय इसके कि या तो वह पुनः संघर्ष करें अन्यथा राजनीतिक जगत में अपनी अवनति स्वीकार करें।

उन्होंने अपने ७६वें जन्म दिन पर २३ दिसंबर १९७८ को दिल्ली में बोट क्लब पर ऐतिहासिक किसान रैली की अध्यक्षता की, जिसे आज़ाद भारत के इतिहास में किसानों और ग्रामीणों की अब तक की सबसे विशाल रैली कहा गया। जनता पार्टी के लड़ते-झगड़ते नेताओं को इस बात पर सहमत होना पड़ा की वह अकेले जनाधार वाले नेता हैं, जिन्हें वापिस लिए जाने की जरुरत है।

२८ जुलाई १९७९

भारत के प्रधानमंत्री।

मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में २४ जनवरी से १६ जुलाई १९७९ तक वित्त मंत्री। इंदिरा कांग्रेस सहित रजनीतिक दलों के गठबंधन के समर्थन से अल्पकालीन सरकार के प्रधानमंत्री बने।

२४ जनवरी को मोरारजी देसाई से सुलह के विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल में उपप्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में एक अल्प अवधि, १६ जुलाई तक, के लिए वापिस आये। २८ फरवरी को सांसद में, अपनी शहर विरोधी और ग्रामीण-झुकाव की धारणा को व्यक्त करने वाला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। वह जानते थे की यह उनकी केवल एक प्रतीकात्मक, बहुत अल्प और अत्यधिक देर से व्यक्त अभिव्यक्ति है, किन्तु जब एक बार वह यह करने की स्थिति में आ चुके थे, तो उन्हें यह करना ही था।

मोरारजी देसाई से मतभेद जारी रहे, प्रभुत्वशाली जनसंघ घटक एवं जगजीवन राम की साजिशों, एवं अपने प्रतिनिधि राजनारायण के सोचे-समझे गलत कार्य-कलापों और कुछ भूतपूर्व समाजवादियों ने जनता पार्टी का विभाजन तय कर दिया। १६ जुलाई को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। एक असम्बद्ध संसदीय गठबंधन के समर्थन के आधार पर राष्ट्रपति एन. संजीवा रेड्डी द्वारा भारत के पांचवे प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित किये गए। २८ जुलाई १९७९ को इंदिरा गांधी की कांग्रेस (आई) के समर्थन से भारत के प्रधानमंत्री बने।

विश्वासमत हासिल करने वाले दिन, विना संसद का सामना किये २० अगस्त १९७९ को कांग्रेस द्वारा इसलिए समर्थन वापिस लिए जाने के चलते त्यागपत्र दे दिया चूँकि वह इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं कर सके कि इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमों को वह वापिस ले लेंगे। १४ जनवरी १९८० तक कामचलाऊ प्रधानमंत्री के तौर पर, लोकसभा के मध्यावधि चुनाव आयोजित होने तक, वह पद पर बने रहे।

१९८०

उनकी पार्टी लोक दल ने लोकसभा की ४१ सीटों पर जीत हासिल की

उत्तर प्रदेश के बागपत से दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। चुनाव नतीजे उनकी पार्टी लोक दल के लिए गहरा आघात थे, लोक दल, जबकि कांग्रेस (आई) के बाद लोक सभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस आई की ३८४ सीटों (वोटों क प्रतिशत ४३) के मुकाबले ४१ संसदीय सीटों पर (राष्ट्रीय वोटों के ९.४ प्रतिशत) ही विजय हासिल कर सकी । शेष जनता पार्टी ने १९ प्रतिशत वोट हासिल किये किन्तु लोकसभा की ३१ सीटों पर ही जीत पाई।

इंदिरा गांधी एक बार फिर विजयी हुई।

१९८१

"इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ़ इंडिया : इट्स कॉज एण्ड क्योर" का प्रकाशन।

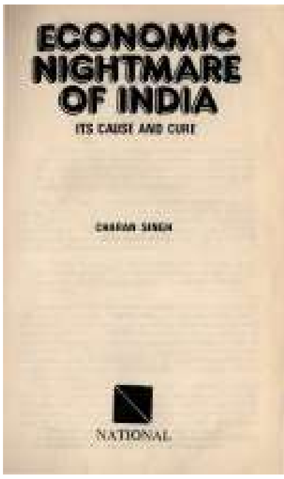

"इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ़ इंडिया : इट्स कॉज एण्ड क्योर" का प्रकाशन।

"वे असामान्य रूप से सफल राजनीतिज्ञ थे। दूसरे, १९४७ और १९८६ के बीच उन्होंने पर्याप्त और ठोस लेखन कार्य किया, जिसके अंतर्गत संगत एवं व्यापक विचारों के आधार पर उन्होंने ग्रामीण भारत की प्रकृति को दर्शाते हुए उस पथ को प्रशस्त किया है, जिस पर ग्रामीण भारत को अग्रसर होना चाहिए। वे सही मायने में बड़े काम के बुद्धिजीवी थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिये विश्लेषण और समाधान का सशक्त सम्मिश्रण प्रस्तुत किया। उस पर भी कृषि मुद्दे में रुचि रखने वाले राजनैतिक अर्थनीति के विशेषज्ञों का विशेष ध्यान जाना चाहिए। सक्रिय राजनीतिक जीवन की अनुपस्थिति में भी ऐसा किया जा सकता है। तीसरे, उनके पास एक ऐसी खूबी थी जिसके आधार पर वे राजनैतिक कर्म के साथ बौद्धिकता को समन्वित करके विचारों का सहज सम्प्रेषण कर सकते थे।" टेरेंस जे. बायर्स (१९८८) चरण सिंह, १९०२-८७ : एन असेसमेंट, द जर्नल ऑफ़ पीजेंट स्टडीज, १५ : २, १३९-१८९

१९८२

लोक दल में टूट।

लोक दल में फूट ; राजनीतिक मतभेदों के चलते उनके कई राजनीतिक साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया।

वह विपक्षी एकता के काम में लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेई के साथ उन्होंने एक चुनावी गठबंधन तैयार किया- पहला राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन- जो कि परस्पर विरोधी राजनीतिक आधार क्षेत्रों के चलते विफल रहा।

नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी (एन.एम.एम.एल.) में रखे १९८२ से १९८४ की अवधि के "द चरण सिंह पेपर्स" भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और बढ़ती असमानता, नेहरू की आर्थिक नीतियां और चरण की दृष्टि में उनकी गलत दिशा दृष्टि और आज़ादी के बाद भारतीय अभिजात्य के सोच की दिशा जैसे मुद्दों के संदर्भ से भरे पड़े हैं। वह भारत के टूटने के प्रति भी भयग्रस्त रहते थे। वह उन्हें विघटनकारी शक्तियाँ कहते थे और पंजाब में सिख समुदाय में उग्रवादी गतिविधियों के विरुद्ध दिलेरी से बोलते थे। वह इंदिरा

गांधी की सरकार द्वारा भिंडरावाले जैसे उग्रवादियों से ढीले-ढाले तरीके से निपटने के खिलाफ थे, वहीँ खालिस्तान की मांग का जोरदार तरीके से खुलेआम विरोध करते थे, जिसके लिए उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियाँ भी मिलीं।

१९८४

इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोध के केंद्र बन गए किन्तु इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को सहानुभूति वोट के रूप में मिली अभूतपूर्व विजय के चलते लोकसभा चुनाव में पार्टी हर गई।

देश के हालात के प्रति तल्लीन रहे। लोक दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान मजदूर पार्टी, उत्कल कांग्रेस तथा अन्य छोटे दलों को मिलाकर २१ अक्टूबर को एक नये दल का गठन किया - दलित मजदूर किसान पार्टी।

३१ अक्टूबर १९८४ को इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। राजीव गांधी ने दिसंबर में हुए लोकसभा चुनाव में भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए ५४२ में से ४११ सीटों पर जीत हासिल की।

इंदिरा गांधी की हत्या से पूर्व उनके शासन के प्रति असंतोष ने चरण सिंह को एक बार फिर विपक्षी शक्तियों के ध्रुवीकरण का केंद्र बना दिया। वह बागपत से तीसरी और अंतिम बार केवल तीन सांसदों के साथ संसद के लिए चुने गये। राजीव गांधी के प्रति "सहानुभूति लहर" में सारा विपक्ष बह गया। एक बार पुनः और अंतिम बार, इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को परास्त कर दिया।

२५ नवंबर १९८५

भयानक मस्तिष्क आघात से पीड़ित जिसने उन्हें अगले १८ माह के लिए अक्षम बना दिया

२५ नवंबर को मस्तिष्क को अक्षम बन देने वाला गहरा आघात, भारत सरकार के खर्चे पर भारत और अमेरिका के सर्वोत्तम डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा की गई किन्तु आंशिक रूप से पक्षाघात के शिकार और असंपृक्त बने रहे। १९८६ तक धीमे-धीमे आंशिक कॉमा की स्थिति में चले गये।

२९ मई १९८७

२९ मई १९८७ को निधन।

२९ मई १९८७ को ८५ वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया,
महात्मा गांधी की समाधि के पास, जिसे अब
"किसान घाट" कहा जाता है, अंतिम संस्कार हुआ।